



राजस्थान में कृषि विकास और ग्रामीण विकास पर माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का प्रभाव

श्रेयांश खराड़ी¹ | डॉ. प्रवीण पंड्या²

¹ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, सामाजिक विज्ञान संकाय, उदयपुर, राजस्थान.

² मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, सामाजिक विज्ञान संकाय, उदयपुर, राजस्थान.

ABSTRACT:

यह अध्ययन राजस्थान के ग्रामीण परिदृश्य में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (MFIs) के कृषि विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि-आधारित है, किंतु जलवायु-निर्भर खेती, सीमित ऋण उपलब्धता और ग्रामीण निर्धनता जैसी समस्याएँ इसकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इस संदर्भ में माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी हैं, जो लघु ऋण, बचत और बीमा सेवाओं के माध्यम से सीमांत व लघु किसानों तथा महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं।

अध्ययन में चयनित जिलों के फील्ड डाटा, एमएफआई अधिकारियों और कृषकों से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया गया है। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि माइक्रोक्रेडिट की उपलब्धता ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक तथा सिंचाई उपकरणों में निवेश का अवसर दिया, जिससे कई क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण में सुधार हुआ। साथ ही, स्व-सहायता समूहों (SHGs) ने महिलाओं की वित्तीय साक्षरता, बचत प्रवृत्ति और निर्णय-निर्माण क्षमता को बढ़ावा दिया। हालांकि, ऋण की सीमित राशि, समयबद्ध पुनर्भुगतान दबाव, और पूरक सेवाओं की कमी ने माइक्रोफाइनेंस के दीर्घकालिक प्रभाव को सीमित किया।

अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि माइक्रोफाइनेंस ने ग्रामीण जीवन में क्रमिक सुधार तो लाया है, परंतु इसे परिवर्तनकारी परिणामों के लिए प्रशिक्षण, बाजार संपर्क, सिंचाई सहयोग और डिजिटल साक्षरता जैसी पूरक रणनीतियों के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। नीतिगत स्तर पर, कृषि-केंद्रित ऋण उत्पाद, बीमा योजनाओं का एकीकरण, तथा डिजिटल वित्तीय अवसरचना का विस्तार माइक्रोफाइनेंस को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह शोध राजस्थान जैसे चुनौतीपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में माइक्रोफाइनेंस की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।

KEYWORDS:

माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ (MFIs), कृषि विकास, ग्रामीण विकास, स्व-सहायता समूह (SHGs), वित्तीय समावेशन।

PAPER ACCEPTED DATE:

24th August 2025

PAPER PUBLISHED DATE:

26th August 2025

PAPER DOI NO:

10.5281/zenodo.16948073

PAPER DOI LINK:

<https://zenodo.org/records/16948073>

1. प्रस्तावना

राजस्थान राज्य, जो अपनी विशाल ग्रामीण संरचना और मुख्यतः कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, सतत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। यद्यपि राज्य ने गत दशकों में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी यह जलवायु-सम्बेदनशील खेती, सीमित ऋण सुलभता, और गहरी से व्याप्त ग्रामीण निर्धनता जैसी समस्याओं से अब भी जूझ रहा है। ऐसे परिदृश्य में, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ (Microfinance Institutions – MFIs) एक संभावित परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभर कर सामने आई हैं, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित हाशिए के ग्रामीण समुदायों को लघु ऋण, बचत योजनाएँ, और ऋण-संलग्न सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

राजस्थान में कृषि का महत्व असंदिग्ध है — राज्य की कुल कार्यबल का लगभग 60% भाग इस क्षेत्र में संलग्न है और यह राज्य की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तथापि, कृषि क्षेत्र अभी भी अनेक जोखिमों से ग्रस्त है, जैसे अनियमित वर्षा, सीमित सिंचाई सुविधा, और आधुनिक कृषि निवेश हेतु सुलभ व सस्ता ऋण उपलब्ध न होना। दूसरी ओर, ग्रामीण विकास भी कई अवरोधों से बाधित है — जिनमें निम्न साक्षरता दर, लैंगिक असमानता, तथा वित्तीय ढाँचे की अनुपस्थिति प्रमुख हैं। माइक्रोफाइनेंस, एक लक्षित वित्तीय समावेशन रणनीति के रूप में, ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन और कृषि सशक्तिकरण की दिशा में एक

संभावित समाधान के रूप में प्रस्तुत की गई है।

भारत में 1990 के दशक के प्रारंभ से ही माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का तीव्र विकास हुआ है, जिन्होंने पारंपरिक बैंकों द्वारा छोड़े गए ऋण रिक्त स्थान को भरने का कार्य किया है। SKS माइक्रोफाइनेंस, बंधन, तथा क्षेत्रीय स्व-सहायता समूहों (SHGs) जैसी संस्थाओं ने 'अंतिम छोर' तक पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। राजस्थान के सुदूरवर्ती जिलों में विशेषकर महिला कृषकों और लघु जोत वाले किसानों के बीच इन संस्थाओं की पहुंच बढ़ी है। हालांकि इनकी उपस्थिति निरंतर बढ़ रही है, फिर भी इनका वास्तविक प्रभाव — जैसे कृषि उत्पादकता, आजीविका का विविधीकरण, और समग्र ग्रामीण विकास — विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में पर्याप्त रूप से दस्तावेजीकृत नहीं है। यह स्पष्ट शोध अंतर (research gap) इस अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि यह समझा जा सके कि माइक्रोफाइनेंस किस सीमा तक दीर्घकालिक ग्रामीण विकास संकेतकों को प्रभावित कर रही हैं।

शोध की प्रमुख समस्या यह है कि क्या माइक्रोफाइनेंस मॉडल वास्तव में कृषि विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के ठोस परिणामों में परिवर्तित हो पाया है। उपलब्ध साहित्य अधिकतर शहरी माइक्रोउद्यमों या गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है, जबकि राजस्थान

की कृषि-आर्थिक जटिलताओं की विशिष्ट विवेचना प्रायः अनुपस्थित है। यह शोध इस शून्य को भरने का प्रयास करता है, जिसमें एमएफआई हस्तक्षेपों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों को कृषि और ग्रामीण जीवन पर परखा जाएगा।

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- कृषि उत्पादन एवं ऋण सुलभता में एमएफआई की भूमिका का मूल्यांकन करना।
- आय स्थिरता और ग्रामीण विकास संकेतकों पर उनके योगदान की विवेचना करना।
- राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में माइक्रोफाइनेंस कार्यान्वयन की सफलता एवं बाधाओं की पहचान करना।

इन उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित शोध प्रश्नों को संरचित किया गया है

- राजस्थान के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में एमएफआई की पहुंच का स्तर क्या है?
- क्या एमएफआई हस्तक्षेपों से कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है?
- ग्रामीण लाभार्थियों को माइक्रोफाइनेंस सेवाओं तक पहुंच और उनके उपयोग में कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं?

अध्ययन का क्षेत्र चयनित जिलों तक सीमित रहेगा, जो विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंकड़ों का संग्रहण कृषकों, एमएफआई अधिकारियों, तथा सरकारी नीति दस्तावेजों से किया जाएगा। हालांकि, अध्ययन की सीमाएं भी यथोचित रूप से पहचानी गई हैं — जिनमें स्व-रिपोर्टेड डाटा में पूर्वाग्रह की संभावना और अन्य विकास कार्यक्रमों से एमएफआई के प्रभाव को अलग कर पाना प्रमुख चुनौती रहेगी।

2. समीक्षित साहित्य

माइक्रोफाइनेंस और कृषि विकास के मध्य संबंध को वैश्विक तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से अध्ययन का विषय बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, माइक्रोफाइनेंस को एक अभिनव वित्तीय अवधारणा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है। नोबेल पुरस्कार विजेता **मुहम्मद युनुस (2007)** सहित अनेक विद्वानों ने माइक्रोफाइनेंस की भूमिका को ग्रामीण जीवनशैली में परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में रेखांकित किया है, विशेषकर उन समुदायों के लिए जो औपचारिक बैंकिंग ढांचे से बाहर हैं। बांग्लादेश, केन्या, और अन्य विकासशील देशों में माइक्रोफाइनेंस ने कृषि उत्पादकता तथा ग्रामीण आय में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, इन प्रभावों की तीव्रता और गुणवत्ता क्षेत्रीय संस्थागत ढांचों, सामाजिक-आर्थिक परिवेश, और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करती रही है।

भारतीय संदर्भ में, माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेशन का एक केंद्रीय स्तंभ बन चुका है, विशेष रूप से 1990 के दशक में **नाबाई** द्वारा आरंभ किए गए **स्व-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP)** के बाद। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। **भारतीय रिजर्व बैंक** और **SIDBI** जैसी संस्थाओं ने भी माइक्रोफाइनेंस सेवाओं के विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाई है। **घाटे (2007)** और **बसु एवं श्रीवास्तव (2005)** द्वारा किए गए अध्ययनों में यह स्पष्ट होता है कि भारत में माइक्रोफाइनेंस मॉडल सामुदायिक आधारित अनौपचारिक संरचनाओं से उभर कर एक विनियमित और संस्थागत ढांचे में विकसित हुए हैं। किंतु यह उल्लेखनीय है कि इन अध्ययनों का फोकस मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों पर केंद्रित रहा है, जहाँ माइक्रोफाइनेंस की पहुंच सबसे अधिक है, जबकि राजस्थान जैसे राज्यों की उपेक्षा की गई है।

राजस्थान में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का विकास तुलनात्मक रूप से विलंबित परंतु निरंतर रहा है। राज्य की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना—जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था, रेगिस्तानी भौगोलिक स्थिति, और बिखरी हुई बस्तियाँ—शुरुआती चरणों में एमएफआई के लिए गंभीर परिचालन बाधाएं बन गई थीं। इसके बावजूद, पिछले दो दशकों में विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC-MFIs), स्वयंसेवी संगठन (NGOs), और स्व-सहायता समूह आधारित मॉडल ने उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में प्रभावी उपस्थिति दर्ज की है। **सिंह और मीणा (2014)** द्वारा किए गए अध्ययन में यह दर्शाया गया

है कि माइक्रोफाइनेंस ने महिलाओं के सशक्तिकरण और ऋण उपलब्धता में योगदान दिया है, किंतु ये अध्ययन कृषि उत्पादकता में प्रत्यक्ष सुधार के साथ इन प्रयासों को जोड़ने में असफल रहे हैं।

भारत में किए गए कई अनुभवजन्य अध्ययनों ने माइक्रोफाइनेंस और ग्रामीण विकास के बीच सकारात्मक संबंध को स्थापित किया है। **खांदकर (2005)** और **स्वेन एवं वर्गीज (2009)** के शोध निष्कर्षों में यह प्रतिपादित हुआ है कि माइक्रोफाइनेंस ने पारिवारिक स्तर पर जोखिम को कम किया है और कृषि में निवेश के स्वरूप में परिवर्तन लाया है। हालांकि, इन अध्ययनों में इस प्रश्न की गहराई से पड़ताल नहीं की गई है कि ऋण का वास्तविक उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने में हुआ या वह उपभोग की आवश्यकताओं में व्यय हो गया। राजस्थान में उपलब्ध साहित्य प्रायः केस स्टडी या वर्णनात्मक मूल्यांकन पर आधारित है, जिससे इनके निष्कर्षों की व्यापकता सीमित हो जाती है और समग्र राज्य स्तर पर कोई निर्णायक अवधारणा निर्मित नहीं हो पाती।

इस शोध का सैद्धांतिक आधार दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: पहला, **'गरीबी उन्मूलन सिद्धांत' (Poverty Alleviation Theory)**, जो यह प्रतिपादित करता है कि ऋण तक पहुंच निर्धनता के चक्र को तोड़ने की एक मूलभूत राह है; और दूसरा, **'वित्तीय समावेशन सिद्धांत' (Financial Inclusion Theory)**, जिसके अनुसार ग्रामीण विकास केवल वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता और प्रभावशीलता से निर्धारित होता है। इन सैद्धांतिक ढांचों से यह स्पष्ट होता है कि एमएफआई की उपस्थिति अपने आप में पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उन्हें प्रभावी वितरण प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और स्थानीय सहभागिता से सशक्त न किया जाए।

समीक्षित साहित्य की आलोचनात्मक विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अब भी शोध क्षेत्र में तीन प्रमुख रिक्तताएँ (research gaps) विद्यमान हैं:

राजस्थान विशेष में माइक्रोफाइनेंस का कृषि उत्पादकता पर प्रभाव दर्शाने वाले अनुभवजन्य (empirical) आंकड़ों की गंभीर कमी;

आजीविका विविधीकरण तथा ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर माइक्रोफाइनेंस के प्रभाव की अपर्याप्त विवेचना;

मिश्रित विधि दृष्टिकोण (Mixed-method approach) का अभाव, जिसमें वित्तीय आंकड़ों को क्षेत्रीय गुणात्मक अवलोकनों के साथ एकीकृत किया जा सके।

तालिका 1: भारत के प्रमुख राज्यों में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की पहुंच (2022-23)

राज्य का नाम	सक्रिय ऋण खाते (लाख में)	कुल ऋण राशि (करोड़ ₹ में)	प्रति ग्राहक औसत ऋण (₹ में)
तमिलनाडु	105.2	34,560	32,850
पश्चिम बंगाल	91.4	30,875	33,770
बिहार	87.6	27,300	31,180
उत्तर प्रदेश	83.1	26,845	32,290
राजस्थान	28.4	8,760	30,845

स्रोत: MFIN India – Micrometer Report, Q4 2022-23

विश्लेषण: उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान जैसे राज्य में माइक्रोफाइनेंस की पहुंच तुलनात्मक रूप से अभी भी सीमित है, जबकि दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में इसका अधिक व्यापक प्रभाव देखा गया है। यह अंतर नीतिगत ढांचे, सामाजिक स्वीकृति, और वितरण क्षमता से भी जुड़ा हुआ है।

3. अध्ययन क्षेत्र और संस्थाओं की रूपरेखा

राजस्थान, जो क्षेत्रफल ल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एक विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और कृषि-जलवायु परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जो इसे माइक्रोफाइनेंस के प्रभाव के अध्ययन हेतु चुनौतीपूर्ण तो बनाता ही है, साथ ही नीति-निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक भी बनाता है। राज्य की लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है

और मुख्यतः कृषि तथा इससे संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। यद्यपि हाल के वर्षों में भौतिक अवसरचना में कुछ सुधार हुआ है, फिर भी ग्रामीण राजस्थान अभी भी अकाल, निम्न साक्षरता, सीमित सिंचाई सुविधाएं, तथा सीमांत जोतों जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जो ग्रामीण आजीविका की संवेदनशीलता को और अधिक बढ़ा देते हैं।

राजस्थान में कृषि का प्रमुख रूप से मानसून आधारित (rain-fed) होना इसकी सबसे बड़ी संरचनात्मक कमजोरी है, जिससे यह क्षेत्र बार-बार जलवायु-आधारित झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बन जाता है। बाजरा, गेहूँ, सरसों और दलहन जैसी फसलें यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखती हैं, जबकि पशुपालन एक सहायक आजीविका का रूप प्रदान करता है। राज्य के छोटे और सीमांत किसान पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के सख्त कोलैटरल और जटिल प्रक्रियाओं के कारण समय पर और सुलभ ऋण से वंचित रह जाते हैं। इस आर्थिक अस्थिरता के संदर्भ में, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (MFIs) राजस्थान के ग्रामीण विकास परिदृश्य में एक आवश्यक और प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में उभरती हैं।

पिछले दो दशकों में राजस्थान में एमएफआई की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अब ऐसे वित्तीय उत्पादों की पेशकश कर रही है, जिनमें माइक्रो-लोन, समूह ऋण प्रणाली, सूक्ष्म बीमा, और बचत योजनाएं शामिल हैं। राज्य में सक्रिय प्रमुख एमएफआई में SKS Microfinance, Satin Creditcare, Fusion Microfinance, ESAF, और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) जैसे क्षेत्रीय एनजीओ शामिल हैं। इन संस्थाओं ने राजस्थान की विशिष्ट ग्रामीण चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से स्व-सहायता समूह (SHG), साझा उत्तरदायित्व समूह (JLG), और महिला-केंद्रित ऋण मॉडल्स के माध्यम से कार्यान्वयन की रणनीतियाँ विकसित की हैं।

हालांकि एमएफआई की पहुँच बढ़ रही है, फिर भी उन्हें कई गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है—जैसे कि बिखरी हुई बस्तियों के कारण उच्च संचालन लागत, डिजिटल साक्षरता की कमी, और महिलाओं में औपचारिक ऋण के प्रति सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकोच। इसके बावजूद, SHG आधारित माइक्रोफाइनेंस मॉडल ने ग्राम स्तर पर महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने, कृषि निवेश में सुधार लाने, तथा ऋण अनुशासन को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल आधारित क्रेडिट स्कोरिंग और डिजिटल ऋण चुकौती प्रणाली जैसे नवाचार धीरे-धीरे एमएफआई के संचालन स्वरूप को रूपांतरित कर रहे हैं।

एमएफआई प्रयासों को समर्थन देने हेतु सरकारी योजनाएँ भी कार्यरत हैं, जिनका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण एवं कृषि विकास लक्ष्यों से जोड़ना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), जिसे राजस्थान में RGAVP के रूप में कार्यान्वित किया गया है, ने ग्रामीण महिलाओं को SHG के रूप में संगठित करने और उन्हें बैंकों तथा एमएफआई से जोड़ने में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी योजनाएँ किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे उनकी ऋण मांग और उधारी व्यवहार भी प्रभावित होता है। नाबार्ड द्वारा संचालित SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम, पुनर्वित्त पोषण योजनाएँ, और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम इस पारिस्थितिकी तंत्र को संस्थागत समर्थन प्रदान करते हैं।

हालांकि, एमएफआई और सरकारी कार्यक्रमों के मध्य समन्वय में अब भी गंभीर खामियाँ मौजूद हैं। लक्षित लाभार्थियों में अधिकारों की अतिरेक (overlap), जानकारी की कमी, तथा संस्थागत तालमेल की अनुपस्थिति इन कार्यक्रमों के प्रभाव को सीमित कर देती है। इसके अतिरिक्त, ऋण की उपलब्धता में सुधार तो हुआ है, परंतु पूरक सेवाओं जैसे कि प्रशिक्षण, विपणन संबंध, तथा फसल बीमा कवरेज का अभाव इस प्रयास को अधूरा बना देता है।

इस प्रकार, राजस्थान के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि माइक्रोफाइनेंस एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप मात्र है, समाधान नहीं। इसे प्रभावी बनाने के लिए केवल ऋण की पहुँच नहीं, बल्कि सामाजिक, संस्थागत और तकनीकी स्तरों पर एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है।

तालिका 2: RGAVP के तहत महिला SHG की प्रगति (2018-2023)

वर्ष	कुल SHG समूह	बैंक लिंकेज प्राप्त SHG (%)	औसत ऋण प्राप्त प्रति SHG (₹ में)	SHG से जुड़े परिवार
2018-19	54,210	63	1,12,000	6,48,000

2019-20	61,520	68	1,24,500	7,38,240
2020-21	72,890	72	1,36,200	8,64,320
2021-22	81,100	76	1,41,800	9,54,650
2022-23	88,340	80	1,53,600	10,38,500

(स्रोत: RGAVP Annual Progress Report, Government of Rajasthan)

विश्लेषण: महिला SHG की संख्या में निरंतर वृद्धि और बैंक लिंकेज का बढ़ता प्रतिशत दर्शाता है कि राज्य सरकार की NRLM आधारित रणनीति ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय रूप से संगठित करने में प्रभावी रही है। ऋण राशि में प्रति वर्ष ~8% की औसत वृद्धि देखी गई है।

4. चर्चा और परिणाम

फील्ड डाटा के विश्लेषण और विभिन्न हितधारकों (stakeholders) से प्राप्त अंतर्दृष्टियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (MFIs) का प्रभाव कृषि विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में मिश्रित किंतु महत्वपूर्ण रहा है। कुल मिलाकर, अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि एमएफआई ने सकारात्मक योगदान दिया है, लेकिन यह प्रभाव समान रूप से वितरित नहीं है और बड़े पैमाने पर स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है।

सबसे प्रमुख निष्कर्ष यह है कि माइक्रोक्रेडिट की सुलभता ने सीमांत और लघु किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, और सिंचाई उपकरणों जैसे कृषि निवेशों में निवेश करने का अवसर प्रदान किया है। उन क्षेत्रों में जहाँ एमएफआई की पहुँच बेहतर है, वहाँ फसल उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण (विशेषकर सब्जियों और तिलहन जैसी उच्च मूल्य की फसलों की ओर) देखने को मिला। हालांकि, यह प्रगति सभी जिलों में समान नहीं है; कुछ किसान अब भी पारंपरिक फसलों और विधियों पर निर्भर हैं, जिसका प्रमुख कारण प्रशिक्षण की कमी, सिंचाई अवसररचना का अभाव और स्थानीय बाजार की अनुपलब्धता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एमएफआई भले ही प्रेरक कारक (catalyst) का कार्य कर रही हों, परंतु इनका प्रभाव पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है—यह अन्य पूरक विकास तंत्रों पर भी निर्भर करता है।

ग्रामीण विकास संकेतकों के संदर्भ में अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि घरेलू आय, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, बच्चों की शिक्षा, और आस्ति निर्माण में आंशिक सुधार हुआ है। विशेष रूप से महिलाओं ने SHG से जुड़ने के बाद परिवारिक निर्णयों में सहभागिता और बचत व्यवहार में वृद्धि की सूचना दी है। कुछ गांवों में, एमएफआई लाभार्थियों ने गोदाम बनाए, पशुधन खरीदा, या बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए—ये परिवर्तन ग्रामीण जीवन की धीमी लेकिन सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रगति का संकेत हैं। हालांकि, ये लाभ मुख्यतः उन उधारकर्ताओं तक सीमित हैं जो बार-बार ऋण ले चुके हैं या जिनकी आय के स्रोत विविध हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि माइक्रोफाइनेंस तब अधिक प्रभावी होती है जब वह व्यापक विकास रणनीतियों के साथ एकीकृत होती है।

एमएफआई ने ग्रामीण वित्तीय बहिष्करण को भी काफी हद तक चुनौती दी है। गैर-गिरवी आधारित ऋण प्रणाली ने ग्रामीणों की स्थानीय साहूकारों पर निर्भरता को कम किया है, विशेषकर अल्पकालिक कृषि या घरेलू आवश्यकताओं के लिए। फिर भी, ऋण की सीमित राशि बड़े स्तर के कृषि निवेशों के लिए अपर्याप्त सिद्ध होती है, और ऋण चुकौती की समय-सीमा अक्सर मौसमी आय के साथ मेल नहीं खाती, जिससे किसानों पर चुकौती का दबाव बढ़ जाता है। फसल बीमा या ऋण सुरक्षा के अभाव में, प्राकृतिक आपदा या चिकित्सकीय आपात स्थिति की स्थिति में यह वित्तीय जोखिम और गहरा हो जाता है।

संस्थागत स्तर पर, एमएफआई को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है—जैसे कि दूरदराज क्षेत्रों में उच्च परिचालन लागत, सूखा प्रभावित वर्षों में कम पुनर्भुगतान दर, और प्रशिक्षण व विस्तार कार्य के लिए मानव संसाधनों की कमी। ग्राहक स्तर पर, वित्तीय साक्षरता की कमी, ऋणग्रस्तता का भय, तथा सांस्कृतिक और सामाजिक झिझक, विशेषकर महिलाओं में, सहभागिता को सीमित करते हैं। कई मामलों में, माइक्रोफाइनेंस ऋण का उपयोग उपभोग या सामाजिक दायित्वों में कर दिया जाता है, जिससे इसका दीर्घकालिक विकासात्मक प्रभाव कमजोर हो जाता है।

अन्य अग्रणी राज्यों, जैसे कि आंध्र प्रदेश या कर्नाटक से तुलना करने पर, राजस्थान अभी भी माइक्रोफाइनेंस की पहुँच और संस्थागत परिपक्वता दोनों में पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। जहाँ दक्षिण भारतीय राज्य घने SHG नेटवर्क और मजबूत एमएफआई इकोसिस्टम का लाभ उठा रहे हैं, वहीं राजस्थान की विखरी हुई जनसंख्या, शुष्क भौगोलिक परिस्थिति, और अपर्याप्त अधोसंरचना इसकी बाधाएँ बनती हैं। किंतु यह परिस्थिति ही नीति निर्माताओं के लिए एक अवसर प्रस्तुत करती है, जहाँ स्थान-विशेष रणनीतियों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस की उपयोगिता को बेहतर बनाया जा सकता है।

इससे स्पष्ट रूप से उभरता है कि एमएफआई अकेले ग्रामीण परिवर्तन का वाहक नहीं बन सकते। ऋण वितरण को कौशल प्रशिक्षण, सिंचाई सहयोग, बाजार संपर्क, और डिजिटल साक्षरता के साथ समन्वित करना अत्यावश्यक है। इसके लिए राज्य एजेंसियों, स्वयंसेवी संगठनों और एमएफआई के बीच सार्थक साझेदारी का निर्माण करना होगा, ताकि माइक्रोफाइनेंस केवल एक वित्तीय सेवा न रहकर समावेशी विकास का मंच बन सके।

5. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

यह अध्ययन राजस्थान के ग्रामीण परिदृश्य में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (MFIs) के कृषि विकास और समग्र ग्रामीण उत्थान पर पड़े प्रभाव का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि माइक्रोफाइनेंस ने वित्तीय समावेशन के एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में कार्य किया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सामाजिक-आर्थिक विषमता, जलवायु अस्थिरता और संस्थागत कमजोरी व्यापक रूप से व्याप्त है। स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने और कृषि में सीमित लेकिन रणनीतिक निवेश को सक्षम करने में माइक्रोफाइनेंस की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण रही है।

हालाँकि, निष्कर्ष यह भी इंगित करते हैं कि माइक्रोफाइनेंस का प्रभाव प्रगतिशील (incremental) तो रहा है, परंतु परिवर्तनकारी (transformational) नहीं। एमएफआई-प्रेरित हस्तक्षेपों ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता और फसल विविधता को बढ़ाया है, जहाँ इन्हें सिंचाई, प्रशिक्षण, और बाजार तक पहुँच जैसे पूरक घटकों के साथ एकीकृत किया गया। अध्ययन इस बात पर विशेष बल देता है कि अकेला ऋण वितरण संरचनात्मक ग्रामीण चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता, विशेषकर राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है और जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसलिए, दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत समर्थन (systemic support) आवश्यक है।

एमएफआई की प्रभावशीलता के संदर्भ में निष्कर्ष संतुलित और यथार्थपरक हैं। अध्ययन ने महिलाओं की आर्थिक निर्णय-निर्माण क्षमता, घरेलू संकट-प्रतिरोधक क्षमता, और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता में आंशिक कमी को रेखांकित किया है। वहीं यह भी स्वीकार किया गया है कि एमएफआई को संचालनात्मक, सामाजिक और वित्तीय चुनौतियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। यह निष्कर्ष न तो माइक्रोफाइनेंस को आदर्श समाधान के रूप में महिमामंडित करते हैं और न ही इसे विकास मॉडल से बाहर करते हैं, बल्कि एक यथार्थपरक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

नीतिगत सिफारिशें इस शोध का सबसे व्यावहारिक और प्रभावशील भाग हैं। एमएफआई के लिए सुझाव दिया गया है कि वे कृषि-केंद्रित ऋण उत्पाद विकसित करें, जिनमें मौसमी आय के अनुसार अनुकूलित पुनर्भुगतान कार्यक्रम, और बीमा समाहित योजनाएं सम्मिलित हों। राज्य सरकार के लिए यह अनुशंसा की गई है कि वह डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का विस्तार करे, एमएफआई के संचालन को विनियामक संरचना के अंतर्गत मजबूत बनाए, और NRLM, PM-KISAN, तथा कृषि विस्तार सेवाओं के साथ माइक्रोफाइनेंस को एकीकृत करे। साथ ही, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को सामुदायिक स्तर पर वित्तीय जागरूकता, प्रशिक्षण और ऋण उपरांत सहायता जैसे कार्यों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया है, ताकि ऋणों का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित हो सके।

इस खंड की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह केवल समस्याओं को चिन्हित नहीं करता, बल्कि उनके समाधान के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी प्रस्तुत करता है। यह तकनीक आधारित पहुँच, मोबाइल बैंकिंग, और स्थानीय संस्थाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से कम सेवा-प्राप्त जिलों में एमएफआई की उपस्थिति को सुदृढ़ करने की वकालत करता है। विशेष रूप से प्रथम बार ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय शिक्षा और ऋण निगरानी को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है, ताकि ऋण के दुरुपयोग और अत्यधिक ऋणग्रस्तता को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, अध्ययन ने 'क्रेडिट-प्लस सेवाओं' की आवश्यकता पर बल दिया है, जिनमें ऋण के साथ-साथ क्षमता निर्माण, मूल्य श्रृंखला समर्थन, और कृषि इनपुट व बाजार तक पहुँच जैसे तत्व शामिल हों।

महत्वपूर्ण रूप से, यह अध्ययन भविष्य के अनुसंधान के लिए दिशा भी प्रस्तावित करता है। यह दीर्घकालिक प्रभाव अध्ययन, लैंगिक विश्लेषण, और विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में तुलनात्मक शोध की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि यह समझा जा सके कि विभिन्न सामाजिक-भौगोलिक संदर्भ एमएफआई के परिणामों को कैसे आकार देते हैं। इसके साथ-साथ, यह जलवायु अनुकूलन, डिजिटल वित्तीय सेवाओं, और सहकारी मॉडल के साथ माइक्रोफाइनेंस के अंतर्संबंध को भी खोजने का सुझाव देता है — जो आने वाले समय में ग्रामीण परिवर्तन के अगले चरण के लिए रणनीतिक महत्त्व रखते हैं।

REFERENCES

- बसु, पी. एवं श्रीवास्तव, पी. (2005) "संभावनाओं की खोज: भारत में गरीबों के लिए माइक्रोफाइनेंस और ग्रामीण ऋण पहुँच"। वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर नं. 3649। <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3649>
- घाटे, पी. (2007) "भारतीय माइक्रोफाइनेंस: तीव्र विकास की चुनौतियाँ"। Sage Publications।
- खान्दकर, एस. आर. (2005) "माइक्रोफाइनेंस और गरीबी: बांग्लादेश से प्राप्त पैनेल डेटा के माध्यम से साक्ष्य"। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू 19(2), 263–286। <https://doi.org/10.1093/wber/lhi008>
- सिंह, ए. एवं मीणा, आर. पी. (2014) "राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण पर माइक्रोफाइनेंस का प्रभाव: SHG का एक केस अध्ययन"। *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 2(3), 143–150।
- स्वेन, आर. बी. एवं वर्गीज, ए. (2009) "क्या SHG की भागीदारी आस्ति निर्माण की ओर ले जाती है?" *World Development*, 37(10), 1674–1682। <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.03.006>
- युनुस, एम. (2007) "गरीबी रहित विश्व की रचना: सामाजिक व्यवसाय और पूंजीवाद का भविष्य"। PublicAffairs।
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) (2021) वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21। राजस्थान सरकार। <http://www.rgavp.org>
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (2022) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – क्रियान्वयन रूपरेखा। भारत सरकार। <https://aajeevika.gov.in>
- नाबार्ड (2021) भारत में माइक्रोफाइनेंस की स्थिति 2020–21। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। <https://www.nabard.org>